नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 335
दि. 08.04.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: शिक्षामित्रों को राहत

विकास और नागरिकता पर एक साथ कई अहम कदम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में मंगलवार का दिन कई मायनों में अहम साबित हुआ, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक साथ 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा उस निर्णय की हो रही है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी को स्वीकृति दी गई है। सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय में सीधे 10 हजार रुपये प्रति माह की वृद्धि करते हुए इसे 18 हजार रुपये कर दिया है, जबकि अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी इसी माह अप्रैल से लागू होगी, जिससे लंबे समय से आर्थिक दबाव झेल रहे हजारों शिक्षामित्रों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

प्रदेश में वर्तमान में एक लाख 42 हजार 929 शिक्षामित्र कार्यरत हैं, जिनमें से एक लाख 29 हजार 332 के मानदेय में केंद्र का अंश बढ़ाया गया है, जबकि करीब 30 हजार शिक्षामित्रों के अतिरिक्त व्यय का भार राज्य सरकार खुद वहन करेगी। यह निर्णय न केवल शिक्षामित्रों के लिए राहत भरा है, बल्कि यह सरकार की उस नीति को भी दर्शाता है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ उससे जुड़े कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसी तरह प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के लिए भी यह फैसला काफी अहम है, जिनकी संख्या लगभग 24 हजार 716 है और वे 13 हजार 769 विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं।

कैबिनेट बैठक में केवल शिक्षा से जुड़े फैसले ही नहीं लिए गए, बल्कि विकास, निवेश और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए 25 लाख स्मार्ट टैबलेट खरीदने का फैसला किया है। इससे पहले सरकार 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित कर चुकी है, और अब इस नई योजना के तहत मुख्य रूप से अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को

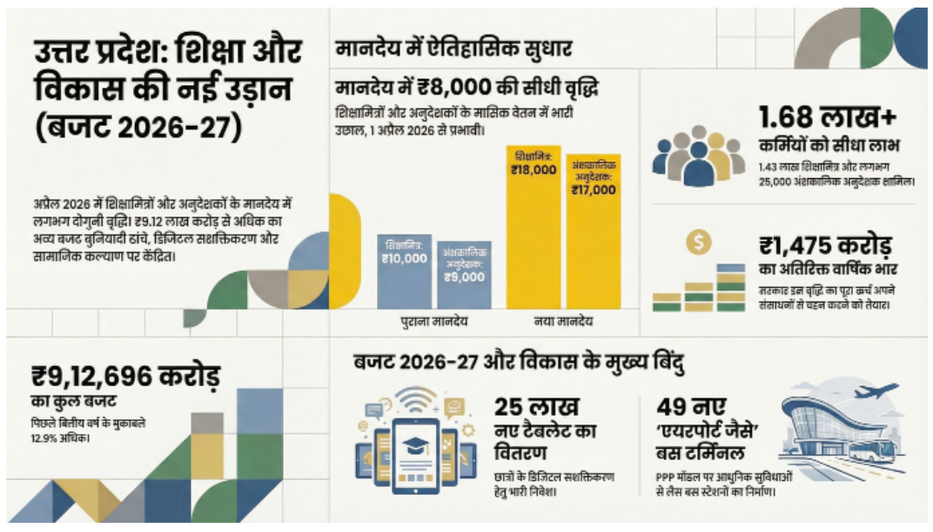

लाभ मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और उन्हें आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना है, ताकि वे प्रतिस्पर्धा के इस दौर में पीछे न रह जाएं।

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भी कैबिनेट ने कई अहम कदम उठाए हैं। बुंदेलखंड में 100 एकड़ भूमि पर सोलर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है, जिससे न केवल क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा प्रयागराज में 231 करोड़ रुपये के निवेश से एक वाटर प्लांट स्थापित करने की योजना को भी हरी झंडी मिल गई है। यह परियोजना शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही सोलर सेल निर्माण इकाई की स्थापना जैसे प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए हैं, जो राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। परिवहन क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के विकास को मंजूरी दी है। इससे पहले पहले चरण में 23 बस अड्डों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, और अब कुल मिलाकर 52 जनपदों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है। इन बस अड्डों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिन्हें एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और राज्य का परिवहन नेटवर्क और अधिक सुदृढ़ होगा।

कैबिनेट के फैसलों में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव उन परिवारों से जुड़ा है, जो भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों—पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर—में आकर बसे थे। ऐसे 12 हजार से अधिक परिवारों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। यह निर्णय दशकों से अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे इन परिवारों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है।

इन सभी फैसलों की जानकारी वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह और वन मंत्री अरुण सक्सेना ने लोकभवन के मीडिया सेंटर में दी। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना भी है, ताकि आम जनता को सीधे लाभ मिल सके।

कुल मिलाकर, यह कैबिनेट बैठक केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह प्रदेश के विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय की दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी जहां एक ओर शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देगी, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसले राज्य के आर्थिक विकास को नई गति देंगे। साथ ही, विस्थापित परिवारों को नागरिकता देने का निर्णय यह दर्शाता है कि सरकार सामाजिक न्याय और मानवीय सरोकारों को भी उतनी ही प्राथमिकता दे रही है।

अब इन फैसलों के क्रियान्वयन पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि किसी भी नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती है। यदि ये सभी योजनाएं तय समय पर और सही तरीके से लागू होती हैं, तो यह न केवल उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा देंगी, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएंगी।

अब हर 'टीनएज प्रेग्नेंसी' का ऑडिट जिम्मेदारों की तय होगी जवाबदेही

बंगलुरू। कर्नाटक सरकार ने राज्य में किशोरियों के बीच बढ़ते गर्भधारण के मामलों को रोकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक और कड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार अब राज्य में होने वाली हर 'टीनएज प्रेगनेंसी' का अनिवार्य रूप से ऑडिट किया जाएगा। यह फैसला न केवल स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके माध्यम से सरकार ने यह संदेश भी दिया है कि किशोरियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति अब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राज्य में किशोरियों के गर्भधारण की संख्या पिछले कुछ वर्षों में चिंताजनक रूप से बढ़ी है। सामाजिक संगठनों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, बाल विवाह, असुरक्षित यौन गतिविधियां, शिक्षा की कमी और सामाजिक जागरूकता की कमी इसके मुख्य कारण हैं। इस गंभीर समस्या को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने न केवल रोकथाम के उपाय अपनाने का निर्णय लिया है, बल्कि अब हर मामले की गहन जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

सरकार के नए आदेश के अनुसार, प्रत्येक 'टीनएज प्रेगनेंसी' की समीक्षा तालुक स्तर पर की जाएगी। तालुक स्वास्थ्य अधिकारी (टीएओ) को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मामले की जांच करनी होगी। इसके लिए अधिकारी को यह देखना होगा कि गर्भधारण किन परिस्थितियों में हुआ, क्या किशोरी को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई और क्या इसमें किसी प्रकार का शोषण या बाल विवाह शामिल था।

टीएओ के साथ-साथ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और स्थानीय समाज कल्याण विभाग भी इस प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। यदि किसी मामले में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य न केवल गर्भधारण के मामलों में तुरंत हस्तक्षेप करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि किसी भी प्रकार की अनदेखी या जाँच में कमी न हो।

कर्नाटक सरकार ने इस आदेश में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के पहलुओं को भी शामिल किया है। हर मामले के ऑडिट के दौरान यह देखा जाएगा कि किशोरी ने समय पर स्वास्थ्य और यौन शिक्षा प्राप्त की थी या नहीं। शिक्षा के अभाव और जानकारी की कमी अक्सर किशोरियों को असुरक्षित परिस्थितियों में डाल देती है।

सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि स्कूलों और कॉलेजों में किशोरियों और उनके अभिभावकों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य किशोरियों को सुरक्षित यौन व्यवहार, गर्भधारण की रोकथाम, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित करना है।

विशेषज्ञों के अनुसार, किशोरियों के गर्भधारण में सबसे बड़ा कारण बाल विवाह और अशिक्षा है। कर्नाटक सरकार ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए स्थानीय पंचायतों और पुलिस विभाग को सक्रिय बनाने का निर्देश दिया है। ऑडिट के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी मामले में बाल विवाह शामिल हो, तो संबंधित परिवार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

बाल विवाह और किशोरियों के गर्भधारण को रोकने के लिए सरकार ने पंचायतों को यह निर्देश दिया है कि वे नियमित निगरानी रखें और किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को दें। इसके साथ ही, पंचायत स्तर पर किशोरियों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समर्थन प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी।

कर्नाटक सरकार का यह कदम केवल जांच और जवाबदेही तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती भी इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर तालुक में किशोरियों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेंटर और हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी, जहां वे सुरक्षित तरीके से जानकारी और चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, गर्भधारण के मामले में समय पर गर्भपात, प्रसूति देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि किशोरियों की सुरक्षा केवल कानूनी कार्रवाई या ऑडिट तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें समग्र स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण की दृष्टि से समर्थन प्रदान करना भी आवश्यक है।

लंबी हिरासत पर कोर्ट की सख्ती: 'महाठग' सुकेश चंद्रशेखर को मिली जमानत, फिर चर्चा में आया 200 करोड़ का मामला

नई दिल्ली। देश के चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में शामिल कथित 'महाठग' सुकेश चंद्रशेखर को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत का यह फैसला केवल एक आरोपी को राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय न्याय व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति को बिना निष्कर्ष के अत्यधिक लंबे समय तक जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

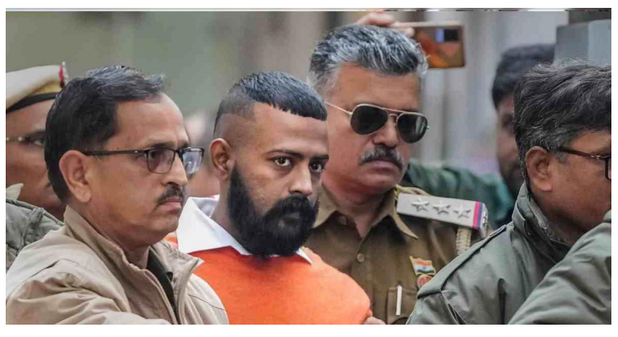

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करना भी है। यदि कोई आरोपी वर्षों तक बिना अंतिम निर्णय के जेल में रहता है, तो यह संविधान द्वारा दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। इसी संवैधानिक सिद्धांत को आधार बनाते हुए कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को जमानत देने का निर्णय लिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते समय कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं, ताकि जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो। अदालत ने निर्देश दिया है कि सुकेश किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा और न ही उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा उसे अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और बिना अदालत की अनुमति के देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। उसे जांच अधिकारी को अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होगा, ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। कोर्ट ने पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर उसकी रिहाई का आदेश दिया है।

यह मामला साल 2021 में सामने आया था, जब तिहाड़ जेल के भीतर से ही एक बड़े ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों के अनुसार, सुकेश चंद्रशेखर ने करीब 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इस पूरे प्रकरण ने उस समय देशभर में सनसनी फैला दी थी, क्योंकि इसमें न केवल बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध शामिल था, बल्कि जेल के भीतर से इस तरह के नेटवर्क के संचालन ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए थे।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि ठगी से हासिल रकम का इस्तेमाल महंगे उपहार देने और हाई-प्रोफाइल संपर्क बनाने में किया गया। इस सिलसिले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज का नाम भी प्रमुख रूप से सुर्खियों में आया था। हालांकि, इस मामले में उनकी भूमिका को लेकर जांच एजेंसियों द्वारा अलग-अलग पहलुओं पर पड़ताल की गई है और यह मामला अब भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है।

सुकेश चंद्रशेखर का मामला केवल एक आर्थिक अपराध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने देश में मनी लॉन्ड्रिंग, जेल प्रशासन और हाई-प्रोफाइल नेटवर्किंग के कई पहलुओं को उजागर किया। यही कारण है कि यह केस लगातार मीडिया और जनता के बीच चर्चा का विषय बना रहा है। अब जब उसे जमानत मिल गई है, तो एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं।

इस फैसले ने एक बार फिर यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी किस हद तक उचित है। अदालत का स्पष्ट संदेश है कि जांच और सुनवाई जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि आरोपी के मौलिक अधिकारों का भी सम्मान किया जाए। कानून का उद्देश्य संतुलन बनाए रखना है—एक ओर अपराध के खिलाफ सख्ती और दूसरी ओर न्याय के सिद्धांतों की रक्षा।

अब देखना यह होगा कि जमानत मिलने के बाद इस मामले की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या जांच एजेंसियां आरोपों को अदालत में साबित कर पाती हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सुकेश चंद्रशेखर की रिहाई ने इस हाई-प्रोफाइल मामले को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है।

सख्त कदम : देशभर में 1 लाख छापे, 52 हजार एलपीजी सिलेंडर जब्त, कालाबाजारी पर सर्जिकल स्ट्राइक

नई दिल्ली। भारत में एलपीजी कालाबाजारी को रोकने और घरेलू गैस की आपूर्ति को नियमित बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने एक अभूतपूर्व सख्त अभियान शुरू कर दिया है। मध्य पूर्व एशिया में जारी युद्ध के कारण एलपीजी सप्लाई पर बढ़ते दबाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाजों के प्रभावित होने के बाद सरकार ने देशभर में एक व्यापक और त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस अभियान के तहत पिछले सप्ताह 1 लाख से अधिक छापे मारे गए और 52,000 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। इसके साथ ही 850 से अधिक एफआईआर दर्ज की गईं और 220 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई न केवल कालाबाजारी रोकने के लिए थी, बल्कि देश में एलपीजी की पारदर्शिता और सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी एक सशक्त कदम है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, एलपीजी कालाबाजारी रोकने की इस कार्रवाई को विशेष अभियान के रूप में लिया गया। इस अभियान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तेल कंपनियों, पुलिस बल और जिला प्रशासन को शामिल किया गया। केंद्र सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति या एजेंसी एलपीजी आपूर्ति में गड़बड़ी या जमाखोरी में लिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

छापेमारी के दौरान एलपीजी वितरकों पर विशेष ध्यान दिया गया। 1,500 से अधिक कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिनमें 118 वितरकों पर जुर्माना लगाया गया और 41 वितरकों को निलंबित किया गया। यह कदम इस बात का संकेत है कि सरकार अब नियमों के उल्लंघन को सहन नहीं करेगी। केंद्रीय अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि जमाखोरी, डायवर्जन या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता को एलपीजी की आपूर्ति में कोई परेशानी न हो।

विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध और अंतरराष्ट्रीय तनाव के इस दौर में घरेलू गैस जैसे आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न बन जाता है। ऐसे समय में जब देश की एलपीजी आपूर्ति का 60 प्रतिशत हिस्सा आयात पर निर्भर है, और उसमें से 90 प्रतिशत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से होकर आता है, किसी भी तरह की गड़बड़ी गंभीर परिणाम ला सकती है।

शिपिंग मंत्रालय के अनुसार, युद्ध के कारण भारतीय ध्वज वाले 16 कार्गो जहाज अब भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के पश्चिम में फंसे हुए हैं। इनमें एक बड़ा एलपीजी लदा जहाज भी शामिल है। इसके अलावा पांच ऑयल टैंकर, एक एलएनजी टैंकर और तीन कंटेनर जहाज भी प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं। इन जहाजों के फंसने से घरेलू आपूर्ति पर दबाव बढ़ा, जिससे कालाबाजारी की संभावना भी बढ़ गई।

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि मौजूदा हालात के बावजूद देश में एलपीजी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कहीं भी सप्लाई पूरी तरह से बंद होने की कोई सूचना नहीं मिली है, और तेल कंपनियां अतिरिक्त स्टॉक और त्वरित वितरण सुनिश्चित कर रही हैं। इसके अलावा सरकार ने एलपीजी डिलीवरी और बुकिंग में डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा दिया है, जिससे पारदर्शिता और आपूर्ति की निगरानी में सुधार हुआ है।

एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग में लगभग 97 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरह, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड आधारित वितरण प्रणाली में लगभग 90 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस डिजिटल माध्यम के प्रयोग से न केवल कालाबाजारी पर रोक लगी है, बल्कि ग्राहकों को अपने सिलेंडर की स्थिति और डिलीवरी की सटीक जानकारी मिल रही है। इससे यह भी सुनिश्चित हो रहा है कि कोई भी परिवार अनावश्यक परेशानियों का सामना न करे।

विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल बुकिंग और ट्रैकिंग सिस्टम ने एलपीजी आपूर्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा दी है। अब कोई भी वितरक या एजेंट अपने व्यक्तिगत हित में गैस सिलेंडरों को डायवर्ट नहीं कर सकता। नागरिक भी अपने मोबाइल और इंटरनेट के जरिए डिलीवरी का सत्यापन कर सकते हैं।

केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि युद्ध और संकट के समय में किसी भी तरह की कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी एलपीजी वितरक या एजेंसी द्वारा नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सरकार ने अपने निगरानी और नियंत्रण तंत्र को और मजबूत कर लिया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के सख्त कदमों से केवल वर्तमान संकट ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी एलपीजी आपूर्ति में अनियमितता और कालाबाजारी पर रोक लगेगी। डिजिटल बुकिंग और ऑथेंटिकेशन कोड आधारित डिलीवरी प्रणाली का इस्तेमाल देश में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस अभियान का सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ा है। सरकार और तेल कंपनियों ने जनता को जागरूक किया है कि एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति नियमित बनी रहे और किसी भी तरह के डर या अफवाह से बचा जा सके। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग करें, सत्यापित वितरक से ही गैस लें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत करें।

विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध और अंतरराष्ट्रीय तनाव के इस दौर में एलपीजी जैसी आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि देश की आपूर्ति श्रृंखला और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती है।

केंद्र सरकार ने एलपीजी आपूर्ति और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें डिजिटल बुकिंग, ऑथेंटिकेशन कोड आधारित वितरण, नियमित ऑडिट और कारण बताओ नोटिस शामिल हैं। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर प्रकार के जमाखोरी, डायवर्जन और अफवाह फैलाने वाले मामलों पर नजर रखें।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई और डिजिटल निगरानी प्रणाली से भविष्य में एलपीजी कालाबाजारी पर काबू पाया जा सकेगा। यह न केवल आम नागरिक के लिए राहत का कारण है, बल्कि देश की आपूर्ति श्रृंखला और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अहम है। मध्य पूर्व के युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के तनावपूर्ण हालात के बीच केंद्र सरकार और तेल कंपनियों द्वारा उठाए गए कदम न केवल तत्काल संकट को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं, बल्कि यह संदेश भी देते हैं कि देश में किसी भी तरह की अनियमितता, कालाबाजारी या जमाखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

मौसम की मार: दो साल से बन रहा पुल ढहा रावी नदी पर लोनिवि की मेहनत बर्बाद

शिमला/चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में रावी नदी पर निर्माणाधीन सियुर पुल मंगलवार सुबह अचानक ध्वस्त हो गया, जिससे क्षेत्र की संचार और कनेक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित हो गई। यह पुल होली से भरमौर के बीच यातायात सुगम बनाने के लिए बनाया जा रहा था और आसपास की कई पंचायतों को जोड़ने का काम कर रहा था। स्थानीय प्रशासन और सड़क निर्माण विभाग की तरफ से बताया गया कि सुबह करीब आठ बजे अचानक पहाड़ी से भारी मलबा और चट्टानें गिरने के कारण पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया और निर्माण सामग्री समेत नदी में बह गया।

लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) ने करीब दो वर्षों से इस पुल पर काम किया था और इस दौरान लगभग चार करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे। अंतिम चरण के कार्य में स्टील रेलिंग का काम पूरा हो चुका था और अधिकारियों का मानना था कि जल्द ही यातायात शुरू किया जा सकेगा। लेकिन अचानक हुई इस आपदा ने विभाग की मेहनत और निवेश को पानी में बहा दिया। भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज ने घटना की पुष्टि करते हुए अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक रास्ते और कनेक्टिविटी के उपाय शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल का ढहना उनके जीवन और रोजमर्रा की गतिविधियों पर गंभीर असर डाल रहा है। बच्चों का स्कूल आना-जाना, बीमारों का अस्पताल जाना और ग्रामीणों का बाजार तक पहुंचना अब मुश्किल हो गया है। व्यापारी और किसान भी पुल टूटने से प्रभावित हुए हैं क्योंकि उनका माल और कृषि उत्पाद अब आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों ने विभाग से मांग की है कि जितनी जल्दी हो सके मरम्मत कार्य शुरू किया जाए और

बारिश और पहाड़ी ढलानों के खतरों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा उपाय किए जाएं।

मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि अगले दो दिनों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना है। शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों में येलो अलर्ट है। अधिकारियों का कहना है कि यह मौसम और भी अस्थिर हो सकता है, इसलिए जनजीवन और सड़क निर्माण के कामों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसानों और बागवानों के लिए यह मौसम और अधिक चिंता का कारण बन गया है। हाल ही में हुई ओलावृष्टि से सेब, सब्जियों और गेहूं की फसल को पहले ही नुकसान हुआ था और अब नई बारिश और तूफानी हवाओं से फसलों का और नुकसान होने की आशंका है। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, जिससे ठंड का असर फिर बढ़ गया है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दी का दौर लौटता दिख रहा है।

स्थानीय प्रशासन और लोनिवि के अधिकारी कह रहे हैं कि पुल की क्षति का आकलन जल्द किया जाएगा और मरम्मत के लिए योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि, भूस्खलन और तेज बहाव वाले रावी नदी की स्थिति के कारण कार्य में देरी की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में निर्माण कार्य हमेशा जोखिम भरा होता है, खासकर जब मौसम अनिश्चित हो और बरसात का सीजन हो।

स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल का निर्माण क्षेत्रीय लोगों की उम्मीदों का केंद्र था। यह पुल न केवल यातायात की सुविधा देने वाला था, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास, पर्यटन और रोजमर्रा के जीवन में भी मददगार होने वाला था। ग्रामीणों का कहना है कि अब जब पुल ढह गया है, तो उन्हें घाटियों और पंचायतों तक जाने के लिए लंबा और खतरनाक रास्ता अपनाना पड़ रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में नदी पर निर्माणाधीन पुलों के डिज़ाइन और निर्माण में स्थानीय भू-भौगोलिक परिस्थितियों, नदी के प्रवाह और मौसम की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। लोनिवि के इंजीनियरों का कहना है कि इस पुल के मामले में मौसम की अचानक बदली और मलबा गिरना एक अनिश्चित प्राकृतिक घटना थी, जिसे सामान्य सुरक्षा उपायों के बावजूद टाला नहीं जा सकता था।

हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि पुल के निर्माण में निगरानी और निर्माण गुणवत्ता पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए था। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि भविष्य में इस तरह की परियोजनाओं में आपदा जोखिम मूल्यांकन और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।

सरकार और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी रास्ते और परिवहन की व्यवस्था जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि पुल के पुनर्निर्माण और सुरक्षा उपायों में तेजी लाकर इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी जल्द बहाल की जाएगी।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पहाड़ी इलाकों में निर्माण कार्य हमेशा मौसम और भू-भाग की चुनौतियों से प्रभावित होता है। लोनिवि, प्रशासन और मौसम विभाग के बीच बेहतर समन्वय, सुरक्षा उपाय और आपदा प्रबंधन रणनीति इस तरह की घटनाओं से निपटने में अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रामीण और पर्यटक दोनों के लिए सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए इस घटना से सबक लिया जाना जरूरी है।

अंततः, रावी नदी पर सियुर पुल का अचानक ध्वस्त होना न केवल भरमौर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बाधित करता है, बल्कि यह याद दिलाता है कि प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित मौसम की मार से निपटने के लिए बेहतर योजना और सतत निगरानी आवश्यक है। स्थानीय प्रशासन, लोनिवि और राज्य सरकार अब इस दिशा में काम कर रही हैं ताकि ग्रामीणों के जीवन और क्षेत्रीय विकास पर असर न्यूनतम हो।

बंदूक नहीं किताब उठाएंगे नक्सली बेल्ट के बच्चे: सुकमा में शिक्षा का नया सूरज

सुकमा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के उन दूरदराज इलाकों में, जिन्हें वर्षों तक नक्सली हिंसा और प्रशासनिक पहुंच की कमी ने शिक्षा और विकास से कटाया रखा, अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक में प्रस्तावित 22 नए स्कूल इस क्षेत्र के बच्चों के लिए शिक्षा का नया द्वार खोलेंगे। वर्षों तक माओवादी 'जनताना स्कूल' के जरिए इस इलाके में अपने विचार फैलाते रहे, लेकिन अब सरकारी प्रयासों के तहत बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा, संविधान की जानकारी और सामाजिक मूल्यों से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है।

बीजापुर और सुकमा के कई वनांचल गांव ऐसे हैं जो दशकों तक प्रशासनिक पहुंच से बाहर रहे। यहां के बच्चे शिक्षा से पूरी तरह वंचित रहे और आज भी कई बच्चों ने जीवन में कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा। कोंटा ब्लॉक इस चुनौतीपूर्ण इलाके में सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां शिक्षा का ढांचा लगभग शून्य हो चुका था। स्थानीय लोगों के अनुसार, बच्चे दिन-प्रतिदिन बड़ी मुश्किलों के बीच जीवन यापन करते थे और शिक्षा के अभाव में उनका भविष्य अनिश्चितता की जद में था। हालांकि, हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों की सक्रियता और प्रशासनिक प्रयासों ने कुछ बदलाव की नींव रखी है। पूववर्ती गांव में गुरुकुल मॉडल की शुरुआत ने एक नई दिशा दिखाई। 20 साल बाद यहां बच्चों ने पहली बार ब्लैकबोर्ड देखा और पढ़ाई की बुनियादी जानकारी प्राप्त की। वर्तमान में गुरुकुल में लगभग 30 बच्चे अध्ययनरत हैं, जबकि शिक्षा विभाग के स्कूल में भी 20 से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है। टेकलागुड़ा और अन्य गांवों में सुरक्षा कैंप की स्थापना के बाद स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ, जिससे बच्चों और परिवारों में नई उम्मीदें जगी हैं। पूर्व नक्सली इलाकों में यह बदलाव और भी महत्वपूर्ण है। बारसा देवा के गांव ओयोपारा में पहले केवल जनताना स्कूल संचालित होते थे, जो बच्चों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखते थे। लेकिन अब शिक्षा विभाग की पहल से बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करने की कोशिश तेज हुई है। देवा का बेटा अब 12वीं की परीक्षा दे चुका है, और गांव के अन्य बच्चों को भी स्कूल से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।

जिला शिक्षा अधिकारी जीआर मंडावी के अनुसार, कोंटा ब्लॉक में प्रस्तावित 22 स्कूलों का उद्देश्य दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है। आवश्यकता पड़ने पर आगे और नए स्कूल भी खोले जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि इन स्कूलों में बुनियादी शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके।

सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह पहल न केवल शिक्षा की दिशा में बल्कि सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। लंबे समय तक हिंसा, डर और असुरक्षा के माहौल में पले-बढ़े बच्चों के लिए शिक्षा केवल किताबें नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और अवसरों का मार्गदर्शन भी है। शिक्षा के माध्यम से बच्चों को बंदूक और हिंसा से दूर रखना, क्षेत्र के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने में मदद करेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा का पुनरुद्धार केवल औपचारिक स्कूल खोलने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसे स्थानीय समुदाय की भागीदारी, शिक्षकों की गुणवत्ता और बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरक वातावरण के साथ जोड़ना आवश्यक है। इसके अलावा, डिजिटल शिक्षा, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की रुचि और सीखने की क्षमता को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण होगा।

स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा की इस नई दिशा से बच्चों के भविष्य के लिए न केवल नए अवसर खुलेंगे, बल्कि इलाके में सामाजिक स्थिरता और विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों के माध्यम से बच्चों में संवैधानिक और नागरिक मूल्यों की समझ बढ़ेगी, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे।

सुरक्षा बलों का सहयोग भी इस योजना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा कैंप और नियमित निगरानी की व्यवस्था की गई है। इससे माता-पिता भी अब बच्चों को स्कूल भेजने में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

सुकमा में इस पहल से यह संदेश भी मिलता है कि बंदूक और हिंसा के बजाय शिक्षा और ज्ञान ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। बच्चों के लिए यह कदम न केवल पढ़ाई का अवसर है, बल्कि उनके जीवन को सकारात्मक दिशा देने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास भी है। प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग का कहना है कि भविष्य में नक्सली प्रभावित अन्य जिलों में भी इसी तरह के स्कूल और शिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। उद्देश्य यह है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे और उन्हें समाज के मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। विशेषज्ञ मानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों में नई सोच, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जागृत होगी, जो लंबे समय में क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण होगी।

सुकमा में किताब की इस नई रोशनी ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षा न केवल ज्ञान देती है, बल्कि समाज में बदलाव की सबसे मजबूत नींव रखती है। बंदूक की जगह किताबें उठाने वाले ये बच्चे आने वाले वर्षों में न केवल अपने जीवन को बदलेंगे, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे।

बरियाही घाट पर त्रासदी: नदी में डूबे तीन सगे भाई, परिवार में मातम पसरा

पटना/समस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे बरियाही गांव और आसपास के इलाकों को स्तब्ध कर दिया है। शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के बरियाही घाट पर मंगलवार की सुबह स्नान करते समय तीन सगे भाइयों की तेज बहाव वाली करेह नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान आदित्य (17), हर्षित (15) और कार्तिक (13) के रूप में हुई है। यह हादसा ऐसे समय में हुआ जब परिवार रामनवमी के अवसर पर पटना और दिल्ली से घर आया हुआ था और नदी के शांत किनारे पर स्नान कर रहे थे।

जानकारी के अनुसार, पिता सुदर्शन कुमार झा, जो दिल्ली में सुरक्षा गार्ड के पद पर तैनात हैं, अपने बच्चों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। अचानक सबसे बड़ा बेटा आदित्य गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए छोटे भाई हर्षित और कार्तिक ने भी छलांग लगाई, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण तीनों एक-एक कर नदी में समा गए। इस दृश्य को पिता की आंखों के सामने घटित होते देख वहां अफरा-तफरी मच गई और आसपास के ग्रामीण मदद के लिए दौड़े।

स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से राहत-बचाव अभियान तुरंत शुरू हुआ। स्थानीय गोताखोरों ने नदी में उतरकर प्रयास किया और आदित्य तथा हर्षित के शवों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सबसे छोटे भाई कार्तिक का शव करीब चार घंटे की खोजबीन के बाद बरामद हुआ। मौके पर पहुंचे प्रभारी अंचल अधिकारी मनीष चौधरी, बीडीओ आलोक कुमार सिंह और थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने राहत और बचाव कार्य की निगरानी की।

यह घटना केवल एक परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए भी भारी सदमे का कारण बनी है। गांव के लोग कहते हैं कि यह घाट हमेशा से स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों का स्थल रहा है, लेकिन गहरे पानी और तेज बहाव के कारण यह सुरक्षित नहीं रहा। पिछले कुछ सालों में नदी में बहने के कई हादसे हो चुके हैं, जिससे यह क्षेत्र लोगों के लिए खतरे का प्रतीक बन चुका है।

प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजे का आश्वासन दिया है। यह मुआवजा मृतकों के परिवार की आर्थिक मदद के साथ-साथ मानसिक सहारा भी प्रदान करेगा। सुदर्शन कुमार झा और उनकी पत्नी इस त्रासदी से बेहद टूट चुके हैं। परिवार का कहना है कि बच्चों की मौत ने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया है और वे इस अपूरणीय क्षति को कभी भुला नहीं पाएंगे।

बरियाही घाट पर यह हादसा इस बात की याद दिलाता है कि प्राकृतिक स्थलों की सुंदरता के साथ-साथ उनका खतरा भी वास्तविक है। स्थानीय प्रशासन ने भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाने, तटबंधों की मजबूती बढ़ाने और नियमित निगरानी रखने की योजना बनाई है। इसके अलावा, ग्रामीणों को भी नदी के खतरनाक हिस्सों के बारे में जागरूक करने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाए जाने की संभावना है।

इस हादसे ने पूरे समस्तीपुर जिले को हिला कर रख दिया है। गांव और आसपास के क्षेत्र में मातम का माहौल है, जबकि स्थानीय प्रशासन और पुलिस राहत कार्यों में जुटी हुई है। तीनों भाइयों का अंतिम संस्कार गांव में पूरे पारिवारिक और सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार किया जाएगा।

विशेषज्ञ कहते हैं कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए न केवल प्रशासनिक प्रयास बल्कि सामुदायिक जागरूकता भी आवश्यक है। बच्चों और युवाओं को नदी और गहरे पानी के खतरों से अवगत कराना, उन्हें तैराकी और बचाव की प्राथमिक जानकारी देना, और सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान करने की आदत डालना अनिवार्य है।

बरियाही घाट पर हुई इस त्रासदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्राकृतिक सौंदर्य के बीच सुरक्षा की अनदेखी कितनी गंभीर परिणाम ला सकती है। आदित्य, हर्षित और कार्तिक की यादें उनके परिवार और गांववासियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। इस हादसे ने सभी को चेताया है कि जलस्रोतों के उपयोग और आनंद के साथ-साथ उनकी सुरक्षा पर भी पूरी सतर्कता बरतनी होगी।

बिहार सरकार का त्वरित कदम: मिडिल ईस्ट में फंसे कामगारों के लिए हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम सक्रिय

पटना। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच बिहार सरकार ने विदेशों में कार्यरत अपने नागरिकों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण और त्वरित पहल की है। विशेष रूप से मिडिल ईस्ट में फंसे बिहारी मजदूरों और कामगारों के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की है और पटना में एक केंद्रीकृत कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ी हुई है।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के नागरिकों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जाए। बैठक में संभावित खतरों, आपात परिस्थितियों से निपटने की रणनीति और विदेशों में फंसे लोगों के लिए तत्काल प्रतिक्रिया तंत्र पर गहन चर्चा की गई। बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि बिहार सरकार की ओर से एक 24 घंटे सक्रिय हेल्पलाइन और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी भी संकट या आपात स्थिति में श्रमिक तुरंत संपर्क कर सकें और त्वरित मदद प्राप्त कर सकें।

कंट्रोल रूम के माध्यम से श्रमिकों को तत्काल सूचना और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग ने इस उद्देश्य के लिए फोन नंबर 0612-2520053 और व्हाट्सऐप नंबर 7368855002 जारी किए हैं। इन नंबरों पर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो चौबीसों घंटे हर प्रकार के मामले—चाहे वह सुरक्षा संबंधी हो, पासपोर्ट और वीज़ा समस्याओं से जुड़ा हो, या यात्रा और स्वास्थ्य आपात स्थितियों से संबंधित हो—में तत्काल सहायता प्रदान करेंगे।

मिडिल ईस्ट में फंसे बिहारी कामगारों की सुरक्षा इस समय अत्यंत संवेदनशील है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को सख्त चेतावनी और 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को लेकर दिए गए अल्टीमेटम ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। इन परिस्थितियों में विदेशों में रह रहे मजदूर और भारतीय नागरिक संभावित जोखिम का सामना कर रहे हैं। बिहार सरकार ने इस खतरे को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और तत्काल मदद के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।

सरकार की यह पहल केवल हेल्पलाइन तक सीमित नहीं है। पटना में स्थापित केंद्रीकृत कंट्रोल रूम के जरिए राज्य सरकार सभी घटनाओं पर निगरानी रख रही है। कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारी स्थिति की समीक्षा करते हैं, आवश्यक कदम उठाते हैं और विदेशों में फंसे श्रमिकों से निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भारतीय विदेश मंत्रालय और स्थानीय भारतीय दूतावासों के साथ भी समन्वय बढ़ाया है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में मदद तुरंत पहुंचाई जा सके।

यह व्यवस्था उन मजदूरों और उनके परिवारों के लिए भी राहत का संदेश है, जो विदेशों में रोजगार के लिए गए हैं और इस समय अनिश्चितता और तनाव के बीच फंसे हुए हैं। बिहार सरकार ने कहा है कि किसी भी आपात परिस्थिति में मजदूरों को न केवल मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि उनके स्थान और सुरक्षित निकासी के लिए भी तुरंत कदम उठाए जाएंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के समय में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया कदम न केवल आपात परिस्थितियों में त्वरित सहायता मुहैया कराता है, बल्कि श्रमिकों के मनोबल और उनके परिवारों में भरोसा भी बनाए रखता है। यह पहल बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल बन सकती है, जिसे अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा सकता है।

इसके साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम में आने वाली हर कॉल और जानकारी का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि किसी भी मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इस योजना के तहत स्वास्थ्य, सुरक्षा, कानूनी सहायता, परिवहन और आवास जैसी सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस बीच, विदेशों में फंसे श्रमिकों और उनके परिवारों ने इस कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार की यह सक्रियता संकट के समय में आश्वासन और सुरक्षा का भरोसा देती है। राज्य सरकार का यह कदम एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे एक राज्य प्रशासन संवेदनशील और जटिल वैश्विक परिस्थितियों में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

गुजरात विक्ट्री फोर्जिंग्स IPO: पूंजी जुटाने के लिए SEBI के पास ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल, नॉन-फेरस मेटल उत्पादों में विस्तार की तैयारी

गुजरात की प्रमुख नॉन-फेरस मेटल उत्पादक कंपनी गुजरात विक्ट्री फोर्जिंग्स लिमिटेड ने पूंजी जुटाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है और अपने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए हैं। कंपनी के इस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के अनुसार, प्रस्तावित IPO में 65 लाख नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि प्रवर्तक विजेंद्रकुमार बिशंबर गुप्ता अपनी हिस्सेदारी का 1.32 करोड़ तक का हिस्सा ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से बेचेंगे। प्रवर्तक का यह कदम अपनी वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में उठाया गया है, ताकि शेयर स्ट्रक्चर में विविधता लाई जा सके और नए निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी लेने का अवसर मिल सके।

कंपनी ने बताया कि IPO से प्राप्त राशि का उपयोग यूनिट-III के विस्तार और कॉपर कैथोड की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में किया जाएगा। इसके अलावा, ताजा निर्गम से प्राप्त राशि का एक हिस्सा कर्ज के भुगतान और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। यह पहल कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के साथ ही उत्पादन में सुधार और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाने में सहायक होगी।

गुजरात विक्ट्री फोर्जिंग्स नॉन-फेरस मेटल उत्पादों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है। कंपनी का उत्पाद पोर्टफोलियो मेटल स्क्रैप की प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग से लेकर हाई-प्योरिटी कॉपर कैथोड, कॉपर ट्यूब और पाइप, कॉपर रॉड, कॉपर बसबार, ब्रास ट्यूब और कॉपर-आधारित मास्टर एलॉय तक विस्तृत है। इन उत्पादों का इस्तेमाल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, निर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नॉन-फेरस मेटल उत्पादों की वैश्विक मांग में निरंतर वृद्धि और भारत में पावर व रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश बढ़ने से कंपनी के IPO में निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है।

कंपनी के IPO के लिए मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल और निर्भय कैपिटल सर्विसेज को बुक-रनिंग लीड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन निवेश बैंकों का काम IPO प्रक्रिया के दौरान निवेशकों से आवेदन लेना, शेयरों का आवंटन करना और रिटेल व इंस्टिट्यूशनल निवेशकों तक प्रक्रिया को सुचारू रूप से पहुंचाना है। प्रवर्तक द्वारा ऑफर फॉर सेल के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचना निवेशकों को अवसर देगा कि वे कंपनी में हिस्सेदारी लेकर दीर्घकालिक लाभ प्राप्त कर सकें।

नॉन-फेरस मेटल उद्योग में गुजरात विक्ट्री फोर्जिंग्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। कंपनी की उत्पादन श्रृंखला में मेटल स्क्रैप की प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग शामिल है, जिससे कच्चे माल की लागत कम होती है और उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर रहती है। कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो की विविधता और उद्योगों में उनकी मांग निवेशकों के लिए इसे और भी आकर्षक बनाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि और नए उद्योगों में प्रवेश से कंपनी की दीर्घकालिक आय में सुधार होगा और शेयरधारकों को स्थिर लाभ मिलेगा।

कंपनी का उद्देश्य अगले तीन वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता दोगुना करना है। इससे न केवल उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, बल्कि कंपनी वैश्विक और घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत करेगी। उद्योग विशेषज्ञ मानते हैं कि नॉन-फेरस मेटल उत्पादों की मांग भविष्य में और बढ़ने की संभावना है, खासकर उन उद्योगों में जहां बिजली, निर्माण, ऑटोमोबाइल और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रों में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। यह स्थिति निवेशकों के लिए स्थिर और दीर्घकालिक लाभ की संभावना बढ़ाती है।

IPO से प्राप्त राशि से यूनिट-III के विस्तार के साथ ही उत्पादन क्षमता में सुधार होगा, जिससे कंपनी बड़ी कॉर्पोरेट परियोजनाओं में भाग लेने और प्रमुख अनुबंध हासिल करने में सक्षम होगी। निवेशकों के लिए यह एक अवसर है कि वे न केवल कंपनी के विकास में हिस्सेदार बनें, बल्कि नॉन-फेरस मेटल उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ अपने निवेश पर दीर्घकालिक लाभ भी अर्जित कर सकें।

गुजरात विक्ट्री फोर्जिंग्स के उत्पादों की गुणवत्ता और उद्योगों में उनकी व्यापक मांग इसे निवेशकों के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बनाती है। कंपनी ने उत्पादन और बिक्री रणनीति में सुधार के लिए कई पहल की हैं, जिनमें उत्पादन क्षमता बढ़ाना, गुणवत्ता नियंत्रण, नई तकनीकों का उपयोग और बाजार विस्तार शामिल है। इन पहलुओं का सीधा असर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और निवेशकों के लाभ पर पड़ेगा।

कंपनी के IPO में निवेश से न केवल नई पूंजी जुटेगी, बल्कि प्रवर्तक को अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा तरल करने का अवसर भी मिलेगा। यह कदम कंपनी के शेयर स्ट्रक्चर में संतुलन लाने और निवेशकों को हिस्सेदारी लेने के लिए आकर्षित करने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत उत्पाद पोर्टफोलियो, बढ़ती मांग और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के चलते यह IPO निवेशकों के लिए आकर्षक रहेगा।

गुजरात विक्ट्री फोर्जिंग्स का यह IPO न केवल कंपनी के विस्तार और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि निवेशकों के लिए भी स्थिर और दीर्घकालिक लाभ का अवसर प्रस्तुत करता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और प्रमुख उद्योगों में मांग के विस्तार के कारण IPO में अच्छी भागीदारी की संभावना है। निवेशकों के लिए यह समय कंपनी में निवेश करने और लाभ प्राप्त करने का अनुकूल अवसर है, जबकि कंपनी अपने विस्तार और उत्पादन क्षमता में सुधार के माध्यम से वैश्विक और घरेलू बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को और मजबूत कर सकेगी।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com* navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

बिहार में जहरीली शराब का कहर: इकलौते कमाऊ बेटे के निधन ने पांच बेटियों को अनाथ बना दिया, मौतों का आंकड़ा 11 तक पहुंचा

मोतिहारी/पटना। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जहरीली शराब ने पिछले छह दिनों में एक परिवार के जीवन को बुरी तरह से तहस-नहस कर दिया है। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालगंगा वार्ड संख्या-29 में सोमवार देर रात 35 वर्षीय जितेंद्र शाह की मौत ने परिवार के लिए दुख और निराशा की सीमाएं पार कर दी हैं। जितेंद्र शाह परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे और उनके निधन के बाद पत्नी ललीता देवी और उनकी पांच बेटियां असहाय और अनाथ हो गई हैं। यह त्रासदी केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रही; जिले में जहरीली शराब पीने से बीते छह दिनों में मृतकों की संख्या 11 तक पहुंच गई है और दर्जनभर से अधिक लोग विभिन्न अस्पतालों में गंभीर हालत में भर्ती हैं।

जितेंद्र शाह के परिवार का कहना है कि उनकी मौत का सीधा संबंध पड़ोस के संजीत शाह द्वारा पिलाई गई शराब से है। 1 अप्रैल की रात, जैसे ही जितेंद्र ने शराब पी, उनकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। परिवार के लोग इसे आपसी रंजिश और स्थानीय विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। परिवार की पांच बेटियों के सामने अब जीवन के कठिन हालात हैं। घर की आर्थिक जिम्मेदारियों से लेकर रोजमर्रा के जीवन तक सभी संकट अचानक परिवार पर आ गए हैं।

इस त्रासदी की शुरुआत 2 अप्रैल से मानी जा रही है। उस दिन जहरीली शराब से प्रभावित होने वाले पहले मामले सामने आए। 4 अप्रैल तक चंदू कुमार, प्रमोद कुमार, परीक्षण मांझी, हीरालाल भगत, लालकिशोर राय, संपत साह और लड्डू साह की मौतें हुईं। 5 अप्रैल को मो. इलियास अंसारी, लड्डू साह (बालगंगा) और जोधा मांझी की मौत हुई। 6 अप्रैल की रात जितेंद्र शाह के निधन के साथ मृतकों की कुल संख्या 11 तक पहुंच गई।

प्रशासन और पुलिस के अनुसार स्थिति अभी भी बेहद गंभीर है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में करीब 15 लोग जहरीली शराब के कारण भर्ती हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। कुछ पीड़ितों की आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ा है, जो इस जहरीली शराब के घातक प्रभाव को दर्शाता है। स्थानीय लोगों और स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि जहरीली शराब का यह घातक असर समुदाय के लिए गंभीर चेतावनी है और इसे नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है।

पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक चौकीदार भी शामिल है। इसके अलावा दो आरोपितों ने अदालत में आत्मसमर्पण किया। आरोपितों पर जहरीली स्प्रिट की बिक्री का आरोप है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि जांच में शामिल सभी जिम्मेदारों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी और इस तरह की घातक बिक्री रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।

स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल राहत उपायों की घोषणा की है। जिलाधिकारी ने मृतकों के परिवारों को सरकारी मुआवजा देने का आश्वासन दिया है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के उपचार के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं। इस घटना ने जिले के गांवों में शराब के अवैध कारोबार और उसकी गंभीरता पर चिंता बढ़ा दी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में जहरीली शराब की यह समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन इसके बढ़ते मामलों ने स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के लिए नई चुनौती पैदा कर दी है। स्थानीय स्तर पर शराब की अवैध बिक्री को रोकने, शराब के सेवन के प्रभावों को रोकने और जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।

मोतिहारी के ग्रामीणों का कहना है कि जहरीली शराब के इस कांड ने समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्य शराब के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। परिवार और स्थानीय समाज अब एक साथ मिलकर इस अवैध कारोबार को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय हो रहे हैं।

इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जहरीली शराब केवल स्वास्थ्य की समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संकट भी पैदा करती है। जितेंद्र शाह जैसे इकलौते कमाऊ सदस्यों की मौत ने परिवार की आय और जीवनयापन को सीधे प्रभावित किया है। पांच बेटियों के लिए अब जीवन की राह कठिन और अनिश्चित हो गई है।

राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अवैध शराब बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा, प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य और जागरूकता अभियान को बढ़ाया जाएगा। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मिलकर ऐसी घटनाओं को दोहराने से रोकने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं।

बिहार में जहरीली शराब से मौतों का यह सिलसिला न केवल स्वास्थ्य संकट को दर्शाता है, बल्कि यह सामाजिक असुरक्षा, गरीबी और अवैध व्यापार की समस्याओं को भी उजागर करता है। जितेंद्र शाह की मौत ने पूरे समुदाय को चेतावनी दी है कि अवैध शराब की बिक्री और सेवन से जुड़े जोखिम गंभीर और जानलेवा हो सकते हैं।

यह मामला केवल मोतिहारी तक सीमित नहीं है। राज्य के अन्य जिलों में भी अवैध शराब की बिक्री और इसके घातक प्रभाव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए व्यापक नीतिगत सुधार, प्रशासनिक सख्ती और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि इस घटना से सबक लेकर अब अवैध शराब के नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ितों को न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

इस तरह, जितेंद्र शाह की मौत और उसके साथ हुई 11 अन्य मौतों की घटना बिहार में जहरीली शराब के खतरनाक प्रभाव की हकीकत को सामने लाती है। यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर चेतावनी है कि अवैध शराब के कारण जीवन और परिवार दोनों ही खतरे में हैं। सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर ऐसे मामलों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे।

झांसे की चाल में उलझे मासूम, गहनों को छोड़ गैस सिलेंडर ले उड़े शातिर

ग्रेटर नोएडा। अपराध की दुनिया में अक्सर चोरी की घटनाएं गहनों, नकदी और कीमती सामान के इर्द-गिर्द घूमती हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 क्षेत्र से सामने आई यह घटना न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि यह भी दिखाती है कि अपराधी किस तरह बदलते हालात के साथ अपनी चालें भी बदल रहे हैं। यहां बदमाशों ने घर में मौजूद कीमती सामान को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि बेहद शातिर तरीके से बच्चों को झांसे में लेकर रसोई में रखे गैस सिलेंडर ही लेकर फरार हो गए।

घटना उस समय की है जब पीड़ित दंपत्ति अपने काम पर बाहर गए हुए थे और घर में उनके दो छोटे बच्चे अकेले थे। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए बाइक सवार बदमाश घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उन्हें सिलेंडर में गैस लीकेज की शिकायत मिली है और तुरंत जांच करनी जरूरी है। बच्चों ने शुरुआत में सतर्कता दिखाते हुए उन्हें अंदर आने से मना कर दिया, लेकिन यहीं से बदमाशों की असली चाल शुरू हुई।

उन्होंने बेहद चतुराई से एक फर्जी कॉल का सहारा लिया और फोन पर बच्चों को उनके पिता जैसी आवाज सुनाई गई,

जिससे बच्चों को यकीन हो गया कि ये लोग सच में गैस एजेंसी से आए हैं। भरोसा बनने के बाद बच्चों ने दरवाजा खोल दिया और बदमाश आराम से घर के अंदर दाखिल हो गए। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का उदाहरण है कि किस तरह अपराधी अब मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं।

घर में घुसते ही बदमाश सीधे किचन की ओर बढ़े। वहां उन्होंने सिलेंडर पर पानी डालकर यह दिखाया कि गैस लीक हो रही है और स्थिति खतरनाक हो सकती है। बच्चों को डराने के बाद उन्होंने कहा कि सिलेंडर को तुरंत बदलना पड़ेगा। मासूम बच्चे कुछ समझ पाते उससे पहले ही दोनों सिलेंडर उठाकर बदमाश तेजी से बाहर निकले और बाइक पर रखकर फरार हो गए।

इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि घर में मौजूद अन्य कीमती सामान को उन्होंने छुआ तक नहीं। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनका लक्ष्य पहले से ही गैस सिलेंडर चोरी करना था, जो मौजूदा समय में बढ़ती कीमतों और काले बाजार की मांग के चलते एक नया "टारगेट" बनता जा रहा है।

जब दंपत्ति घर लौटे और उन्हें घटना की जानकारी हुई, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में बदमाश गैस सिलेंडर ले जाते हुए साफ दिखाई दिए हैं, जिससे उनकी पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

बीटा-2 कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना केवल एक चोरी की वारदात नहीं, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है। खासकर उन परिवारों के लिए, जहां बच्चे घर में अकेले रहते हैं। अपराधी अब सीधे ताकत या हथियार के बजाय दिमाग और धोखे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सतर्कता और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव बन सकती है। आज जरूरत इस बात की है कि बच्चों को भी इस तरह की परिस्थितियों के बारे में जागरूक किया जाए और उन्हें सिखाया जाए कि किसी भी अजनबी पर बिना पुष्टि के भरोसा न करें, चाहे वह कितना ही विश्वसनीय क्यों न लगे। क्योंकि कभी-कभी खतरा वही होता है, जो सबसे सुरक्षित दिखता है।

गंगा की धारा में जाम का शोर, आस्था के बीच उभरी लापरवाही पर सियासी संग्राम

वाराणसी। गंगा, जिसे भारतीय संस्कृति में आस्था, पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है, उसी की लहरों पर जब शोर, नशा और लापरवाही का संगम दिखाई दे, तो यह केवल एक घटना नहीं रह जाती, बल्कि समाज और व्यवस्था दोनों के सामने कई सवाल खड़े कर देती है। वाराणसी में हाल ही में सामने आई एक ऐसी ही घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को आक्रोशित किया, बल्कि पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

बीते रविवार को गंगा नदी के बीच एक नाव पर डीजे की तेज धुनों के बीच कुछ युवक बीयर पीते हुए नाचते नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस मामले में मुख्य आरोपी अर्जुन राजभर को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि वह नाव सजाने का काम करता है और उसी ने इस आयोजन में भूमिका निभाई थी।

घटना उस समय की है जब मांझी समाज के लोग हर साल की तरह बधावा लेकर मिर्जापुर के अदलहाट स्थित शीतला माता मंदिर की ओर जा रहे थे। यह यात्रा परंपरा और आस्था से जुड़ी होती

है, जिसमें लोग श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं। लेकिन इस बार कुछ युवकों ने इस धार्मिक माहौल के बीच ऐसी हरकत कर दी, जिसने पूरे आयोजन की गरिमा को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया।

पुलिस जांच में सामने आया कि अर्जुन राजभर और उसके साथियों ने यात्रा के दौरान नाव के अंदर बीयर पी और डीजे पर डांस किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक हाथ में बीयर की केन लिए हुए हैं और तेज संगीत पर झूम रहे हैं। यह दृश्य गंगा जैसी पवित्र धारा के संदर्भ में लोगों को बेहद आपत्तिजनक लगा, जिसके चलते सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। भेलूपुर थाने में नाविक प्रेम साहनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद डीसीपी काशी गौरव बंसवाल और एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार की निगरानी में पुलिस टीम ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे अस्सी घाट क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस से माफी भी मांगी, लेकिन तब तक मामला काफी बढ़ चुका था।

यह घटना केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि जल्द ही इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या गंगा में शराब पीना अनुमति के दायरे में आता है, क्या इससे धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होतीं, और क्या यह सार्वजनिक व्यवस्था तथा कानूनों का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि कानून के अनुपालन में समानता होनी चाहिए और अलग-अलग मामलों में अलग व्यवहार पर सवाल उठाए।

इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आधुनिकता और मनोरंजन के नाम पर परंपराओं और आस्था की सीमाओं को लांघा जा रहा है। गंगा, जिसे करोड़ों लोग मां के रूप में पूजते हैं, वहां इस तरह की गतिविधियां केवल व्यक्तिगत व्यवहार नहीं रह जातीं, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं से भी जुड़ जाती हैं।

स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करने से पहले सौ बार सोचे। वहीं कुछ लोग इसे युवा वर्ग की लापरवाही और सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह का परिणाम भी मानते हैं, जहां लोग लाइक्स और व्यूज के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं।

फिलहाल, पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला कानून के दायरे में आ चुका है, लेकिन इससे उठे सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं। क्या यह केवल एक व्यक्ति की गलती थी या यह एक बड़ी सामाजिक प्रवृत्ति का संकेत है? क्या आस्था और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखना अब और मुश्किल

बाबा साहब की विरासत पर सियासी संग्राम, 2027 की बिसात पर दलित वोट साधने की नई चाल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सामाजिक न्याय, प्रतीक और रणनीति का संगम देखने को मिल रहा है, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपने-अपने तरीके से दलित समाज के बीच प्रभाव बनाने की कोशिश में जुटे हैं। 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से डॉ. भीमराव अंबेडकर और अन्य महापुरुषों के स्मारकों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण की योजना को मंजूरी दी है, उसने सियासी हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है, जो आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इस योजना के तहत प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित अन्य समाज सुधारकों और सांस्कृतिक विभूतियों के स्मारकों का कायाकल्प किया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 स्मारकों को नई पहचान देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे यह योजना केवल प्रतीकात्मक न रहकर व्यापक स्तर पर प्रभाव डाल सके। सरकार का दावा है कि यह पहल महापुरुषों के सम्मान और उनकी विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से की जा रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने इस योजना को विस्तार देते हुए कहा कि जहां-जहां अंबेडकर और अन्य महापुरुषों की प्रतिमाएं बिना छत्र-चबूतरे के हैं, वहां उनका नवीनीकरण किया जाएगा और व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि

इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल, यानी अंबेडकर जयंती से की जाएगी, जिससे इसका प्रतीकात्मक महत्व और भी बढ़ जाता है।

हालांकि, इस फैसले को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल मूर्तियों का सौंदर्यीकरण करने से दलित समाज का वास्तविक सशक्तिकरण नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने नौकरियों में आरक्षण को कमजोर किया है और अब प्रतीकों के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। सपा ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है और वे बाबा साहब द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में यह योजना एक दुधारी तलवार की तरह है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार का मानना है कि भाजपा इस योजना के जरिए यह संदेश देना चाहती है कि वह भी दलित समाज के हितों के प्रति संवेदनशील है और उन कामों को पूरा कर रही है, जो पहले की सरकारें नहीं कर सकीं। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि यह पहल केवल प्रतीकात्मक रह गई और जमीन पर इसका असर नहीं दिखा, तो इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है।

दूसरी ओर, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह इसे भाजपा की एक सोची-समझी और दीर्घकालिक रणनीति मानते हैं। उनके अनुसार पार्टी ने दलित समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसमें यह योजना एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि यह रणनीति सफल होती है, तो 2027 में भाजपा की सत्ता में वापसी की राह आसान हो सकती है।

दरअसल, इस पूरी रणनीति के पीछे आंकड़ों का भी बड़ा महत्व है। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी लगभग 20.7 प्रतिशत है, जो करीब 4 करोड़ से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस वर्ग के भीतर भी कई उप-जातियां हैं, जिनमें जाटव, पासी, कोरी, धोबी, खटिक और वाल्मीकि जैसी प्रमुख जातियां शामिल हैं। इनमें जाटव समुदाय को परंपरागत रूप से बसपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता है, जबकि गैर-जाटव दलितों में राजनीतिक झुकाव अधिक बंटा हुआ रहा है।

भाजपा ने 2014 से लेकर 2022 तक गैर-जाटव दलित वोटों को अपने पक्ष में करने में सफलता हासिल की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को करीब 8.5 प्रतिशत वोट का नुकसान हुआ। सपा के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले और संविधान व आरक्षण को लेकर बने नरेटिव ने भाजपा के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी। ऐसे में यह नई योजना उसी नुकसान की भरपाई करने की कोशिश के रूप में भी देखी जा रही है।

भाजपा प्रवक्ता हीरो वाजपेई ने इस योजना का बचाव करते हुए कहा कि यह केवल राजनीति नहीं, बल्कि महापुरुषों के सम्मान का कार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने हमेशा महापुरुषों का अनादर किया, जबकि भाजपा सभी वर्गों के प्रतीकों का सम्मान करती है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब केवल नीतियों की नहीं, बल्कि प्रतीकों की भी अहम भूमिका है। मूर्तियों का सौंदर्यीकरण और स्मारकों का विकास केवल सांस्कृतिक या ऐतिहासिक पहल नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक संदेश देने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह योजना वास्तव में दलित समाज के भीतर भाजपा की पकड़ को मजबूत कर पाएगी, या फिर विपक्ष इसे केवल दिखावे की राजनीति साबित करने में सफल रहेगा। 2027 का चुनाव इस सवाल का जवाब देगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बाबा साहब की विरासत एक बार फिर सियासी केंद्र में आ चुकी है और इसके इर्द-गिर्द ही आने वाले समय की राजनीति आकार लेगी।

सुबह से पहले सन्नाटा तोड़ गई छापेमारी, कैराना से चार संदिग्ध हिरासत में, सीमा पार कनेक्शन की जांच तेज

लखनऊ/शामली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाके कैराना में गुरुवार तड़के उस समय हलचल मच गई, जब सूर्योदय से पहले ही एटीएस की टीम ने एक सुनियोजित और गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की। सहारनपुर से पहुंची टीम ने तेजी और सतर्कता के साथ कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत चार संदिग्धों को हिरासत में लिया और प्रारंभिक पूछताछ के बाद उन्हें अपने साथ ले गई। पूरे घटनाक्रम ने इलाके में दहशत और जिज्ञासा दोनों का माहौल पैदा कर दिया है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीरता से जांच रही हैं।

सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई लंबे समय से मिल रही गोपनीय सूचनाओं के आधार पर की गई थी, जिनमें संदिग्ध गतिविधियों और संभावित नेटवर्क के सक्रिय होने के संकेत मिले थे। एटीएस की टीम ने बिना किसी हड़बड़ी के, पूरी रणनीति के साथ छापेमारी को अंजाम दिया, ताकि किसी भी तरह की चूक या सूचना लीक होने की संभावना न रहे। हिरासत में लिए गए लोगों में राशिद और उसकी पत्नी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि राशिद पहले भी नकली करेंसी से जुड़े एक मामले में जेल जा चुका है, जिससे जांच एजेंसियों का शक और गहरा गया है।

जांच एजेंसियां अब इस पूरे मामले को कई एंगल से खंगाल रही हैं। खास तौर पर फर्जी करेंसी नेटवर्क, संदिग्ध लेन-देन और संभावित पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी बड़े खुलासे की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई है, उससे यह साफ है कि मामला सामान्य आपराधिक गतिविधि से कहीं अधिक गंभीर हो सकता है।

कैराना क्षेत्र पहले भी संवेदनशीलता के कारण सुरक्षा एजेंसियों की नजर में रहा है, और इस ताजा कार्रवाई ने एक बार फिर इसे चर्चा के केंद्र में ला दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह-सुबह भारी संख्या में सुरक्षाबलों की मौजूदगी ने सभी को चौंका दिया। कुछ समय के लिए पूरे इलाके में अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया, लेकिन बाद में स्थिति नियंत्रण में रही।

इस ऑपरेशन के बाद स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। क्षेत्र में निगरानी तेज कर दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों से मिल रही जानकारी और तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि हाल के समय में देशभर में फर्जी करेंसी और सीमा पार से जुड़े नेटवर्क को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं। ऐसे में कैराना में हुई यह छापेमारी संभावित रूप से एक बड़े नेटवर्क की कड़ी हो सकती है, जिसकी परतें धीरे-धीरे खुल सकती हैं।

फिलहाल, एटीएस की टीम हिरासत में लिए गए संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है और उनके संपर्कों, कॉल डिटेल्स, बैंकिंग लेन-देन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला कितना व्यापक है और इसके पीछे कौन-कौन से लोग या नेटवर्क सक्रिय हैं।

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं और समय रहते कार्रवाई करने में सक्षम हैं। वहीं, स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। कैराना की इस सुबह ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अब किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश नहीं है और हर छोटी से छोटी सूचना पर भी गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है।

स्मारकों से सशक्त होगा सामाजिक न्याय का संदेश, 403 विधानसभा क्षेत्रों में विरासत संवारने निकली सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के प्रतीकों को नई पहचान देने और उन्हें जनजीवन से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में "डॉ. भीमराव अंबेडकर मूर्ति विकास योजना" को मंजूरी दी गई, जिसके तहत राज्य के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में दस-दस स्थलों का चयन कर उनका व्यापक सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 403 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे हर क्षेत्र में सामाजिक न्याय की विरासत को न केवल संरक्षित किया जाएगा, बल्कि उसे आधुनिक स्वरूप भी दिया जाएगा।

यह योजना केवल पत्थर और प्रतिमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से उन विचारों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है जिन्होंने समाज में समानता, अधिकार और आत्मसम्मान की चेतना जगाई। डॉ. भीमराव अंबेडकर के साथ-साथ संत रविदास, संत कबीरदास, ज्योतिबा फूले और महर्षि वाल्मीकि जैसे महान व्यक्तित्वों से जुड़े स्थलों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि इन महापुरुषों के विचार केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आज के समाज को दिशा देने वाली जीवंत धरोहर हैं।

योजना के तहत प्रत्येक चयनित स्थल पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक खर्च किए जाएंगे। इन स्थानों पर चहारदीवारी, छतरी, हरित विकास, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही स्थानीय कला और शिल्प को प्राथमिकता देकर हर क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य

इन स्थलों को केवल दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और प्रेरणा के केंद्र के रूप में विकसित करना है, जहां नई पीढ़ी इतिहास से जुड़ सके और उससे सीख लेकर आगे बढ़ सके।

इस योजना की एक खास बात यह भी है कि इसमें केवल वे ही स्थल शामिल किए जाएंगे, जो 25 दिसंबर 2025 तक स्थापित हो चुके हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पहले से मौजूद विरासत को सहेजने और मजबूत करने पर ध्यान दिया जाए। प्रथम चरण में सार्वजनिक स्थानों पर स्थित मूर्तियों का उन्नयन किया जाएगा, जिससे आम जनता को सीधे तौर पर इसका लाभ मिल सके।

कैबिनेट बैठक में सामाजिक और सांस्कृतिक पहल के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एक बड़ा निर्णय लिया गया। बलिया जिले में महर्षि भृगु के नाम पर एक नए राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिस पर लगभग 437 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए 14.05 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है। यह मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार लाने का माध्यम बनेगा और स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर प्रदान करेगा।

इसके अलावा, सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी है। इन परिवारों को कानपुर देहात सहित अन्य स्थानों पर बसाने की योजना बनाई गई है, जिससे उन्हें स्थायी आवास और बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सकें। यह निर्णय मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण माना जा रहा है। सरकार का यह कदम केवल विकास योजनाओं का हिस्सा नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें विरासत, सम्मान और समानता को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। स्मारकों का यह कायाकल्प न केवल शहरों और गांवों की तस्वीर बदलेगा, बल्कि समाज में उन मूल्यों को भी मजबूत करेगा, जो लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की नींव हैं। उत्तर प्रदेश में यह पहल ऐसे समय में आई है जब सामाजिक समरसता और ऐतिहासिक चेतना को नई ऊर्जा देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सरकार का मानना है कि जब समाज अपने महानायकों को सम्मान देता है और उनकी विरासत को सहेजता है, तभी वह आगे बढ़ने की सही दिशा तय कर पाता है। यही कारण है कि यह योजना केवल बजट या निर्माण तक सीमित नहीं, बल्कि एक विचारधारा को सशक्त करने का प्रयास है।

इस पहल से यह संदेश भी जाता है कि विकास केवल सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह समाज के विचारों, मूल्यों और इतिहास को भी मजबूत करता है। आने वाले समय में जब ये स्थल विकसित होकर तैयार होंगे, तो वे केवल स्मारक नहीं रहेंगे, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा के जीवंत केंद्र बनेंगे, जहां से समानता, न्याय और सम्मान का संदेश लगातार प्रसारित होता रहेगा।

टैक्स के बोझ तले कराह रही जनता, सरकार पर ऐश के आरोपों से गरमाई सियासत

मंडी। हिमाचल प्रदेश की वादियों में इन दिनों सिर्फ मौसम ही नहीं, सियासत भी तेजी से बदल रही है। एक ओर पहाड़ों की ठंडी हवाएं हैं, तो दूसरी ओर आम आदमी की जिंदगी पर बढ़ते टैक्स और महंगाई की तपिश साफ महसूस की जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति बैठक ने प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे दी है, जहां कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर तीखे सवाल उठाए गए और जनता पर पड़ रहे प्रभाव को केंद्र में रखते हुए सत्ताधारी दल को कठघरे में खड़ा किया गया।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने अपने संबोधन में जिस तरह से सरकार पर आरोपों की बौछार की, उसने साफ संकेत दे दिया कि आने वाले समय में हिमाचल की राजनीति पूरी तरह से जन मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का आम नागरिक दोहरी मार झेल रहा है—एक ओर महंगाई लगातार बढ़ रही है और दूसरी ओर सरकार नए-नए कर और शुल्क लगाकर उसकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। यह स्थिति सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर घर की वास्तविकता बन चुकी है, जहां महीने का बजट संभालना दिन-ब-दिन कठिन होता जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली, पानी और परिवहन जैसी मूलभूत सेवाएं, जो आम आदमी की जिंदगी का आधार होती हैं, अब महंगी होती जा रही हैं। गांवों और कस्बों में रहने वाले लोग, जो पहले से ही सीमित संसाधनों में जीवन यापन करते हैं, अब इन बढ़ती दरों के कारण और अधिक परेशान हैं। खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई है, जहां रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी संघर्ष बनता जा रहा है।

परिवहन व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए। एचआरटीसी के किरायों में बढ़ोतरी और कई रूटों के बंद होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि जीवन की गति को प्रभावित करने वाला संकट बन गया है। स्कूल जाने वाले छात्र, रोजाना काम पर जाने वाले कर्मचारी और छोटे व्यापारियों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से कठिन हो गई है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि राज्य में स्टांप ड्यूटी, सीमेंट की कीमतों और एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी ने न केवल आम आदमी बल्कि व्यापारिक वर्ग को भी प्रभावित किया है। निर्माण कार्य महंगे हो गए हैं, जिससे आम लोगों के घर बनाने के सपने भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं व्यापारियों को बढ़ती लागत के कारण अपने व्यवसाय को चलाना मुश्किल हो रहा है। इसका सीधा असर रोजगार के अवसरों पर भी पड़ रहा है, जिससे युवाओं में निराशा बढ़ रही है। डीजल पर बढ़ाए गए वैट और अतिरिक्त सेस को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि इसका असर केवल परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी के रूप में सामने आ रहा है। खेतों में काम करने वाले किसान से लेकर बाजार में सामान खरीदने वाले उपभोक्ता तक, हर कोई इस बढ़ती लागत का बोझ उठा रहा है।

इस पूरे परिदृश्य में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होती जा रही है और भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात को बढ़ावा मिल रहा है। उनका कहना था कि इससे न केवल शासन की पारदर्शिता प्रभावित हो रही है, बल्कि जनता का भरोसा भी डगमगा रहा है। उन्होंने माफिया गतिविधियों के बढ़ने की बात करते हुए कहा कि यह स्थिति प्रदेश के भविष्य के लिए चिंताजनक है और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

बैठक में मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने भी इन मुद्दों पर अपनी सहमति जताई और संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ जनता के बीच इन विषयों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान तरुण चुग, श्रीकांत शर्मा, संजय टंडन, जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं की मौजूदगी ने इस बैठक को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया।

डॉ. बिंदल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा इन मुद्दों को केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि इसे जनआंदोलन का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है और हर उस मंच पर जनता की आवाज उठाई जाएगी, जहां से सरकार तक संदेश पहुंचाया जा सके।

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में यह घटनाक्रम एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। जहां एक ओर सरकार अपनी नीतियों को विकास और राजस्व संतुलन के लिए आवश्यक बता सकती है, वहीं विपक्ष इसे जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इस टकराव के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि क्या आम आदमी को राहत मिलेगी या वह इसी तरह बढ़ती महंगाई और टैक्स के बोझ के बीच संघर्ष करता रहेगा।

प्रदेश की जनता अब इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। आने वाले समय में यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह चुनावी एजेंडा भी बन सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन आरोपों का किस तरह जवाब देती है और क्या वह जनता को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं। फिलहाल, हिमाचल की सियासत में गर्माहट बढ़ चुकी है और यह साफ है कि आने वाले दिन राजनीतिक रूप से बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं।

आसमान छूते किराए और बढ़ती मजबूरियां हवाई सफर आम आदमी की पहुंच से होता दूर

नई दिल्ली। कभी तेजी, सुविधा और समय की बचत का प्रतीक माना जाने वाला हवाई सफर अब धीरे-धीरे आम आदमी की पहुंच से दूर होता नजर आ रहा है। जिस उड़ान को लोग अपनी जरूरत और सपनों के बीच पुल मानते थे, वही अब बढ़ती कीमतों के कारण एक महंगा विकल्प बनती जा रही है। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी ने विमानन उद्योग की लागत संरचना को पूरी तरह बदल दिया है, जिसका सीधा असर अब यात्रियों की जेब पर पड़ने लगा है।

देश की प्रमुख विमानन कंपनी Air India ने बढ़ती लागत के दबाव को देखते हुए फ्यूल सरचार्ज में संशोधन का निर्णय लिया है, जो 8 अप्रैल से लागू किया जा रहा है। इस फैसले के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही उड़ानों के किराए में वृद्धि तय मानी जा रही है। कंपनी का कहना है कि जेट फ्यूल की कीमतों में हालिया उछाल ने परिचालन लागत को इस हद तक बढ़ा दिया है कि बिना किराया बढ़ाए संचालन को संतुलित करना संभव नहीं रह गया है।

नई व्यवस्था के अनुसार घरेलू उड़ानों के टिकट 299 रुपये से लेकर 899 रुपये तक महंगे हो सकते हैं। यह बढ़ोतरी भले

ही पहली नजर में सीमित लगे, लेकिन नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों और मध्यम वर्ग के लिए यह एक अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने आती है। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बात करें तो यहां किराए में बढ़ोतरी और अधिक तीव्र है, जहां 2,200 रुपये से लेकर 26,000 रुपये तक का अतिरिक्त खर्च यात्रियों को वहन करना पड़ सकता है।

यह केवल एक कंपनी का फैसला नहीं है, बल्कि पूरे विमानन उद्योग में बन रही नई आर्थिक परिस्थितियों का संकेत है। IndiGo पहले ही फ्यूल सरचार्ज में वृद्धि कर चुकी है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में हवाई यात्रा की लागत और बढ़ सकती है। एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे बढ़ती लागत और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें, क्योंकि किराए में अधिक वृद्धि यात्रियों की संख्या को प्रभावित कर सकती है, जबकि लागत में कमी की गुंजाइश सीमित होती जा रही है। इस पूरे परिदृश्य के केंद्र में एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतें हैं, जो विमानन उद्योग के कुल खर्च का एक बड़ा हिस्सा होती हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार जेट फ्यूल की औसत कीमत लगभग दोगुनी होकर 195 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। यह वृद्धि केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस वैश्विक अस्थिरता का परिणाम है, जो पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण पैदा हुई है।

तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल विमानन क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। लेकिन विमानन उद्योग में इसका प्रभाव सबसे तेजी से और सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि यहां ईंधन की लागत सीधे टिकट की कीमतों में जुड़ जाती है। यही कारण है कि जैसे ही एटीएफ महंगा होता है, एयरलाइंस के पास किराया बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।

Air India Express पर भी नई दूरी आधारित ग्रिड प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे किराया निर्धारण की प्रक्रिया और अधिक संरचित हो जाएगी। पहले जहां एक समान सरचार्ज प्रणाली लागू थी, वहीं अब दूरी के आधार पर किराया तय किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि लंबी दूरी की उड़ानों में किराया वृद्धि अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होगी, जबकि छोटी दूरी की उड़ानों पर इसका असर अपेक्षाकृत कम रहेगा।

इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा, जो नौकरी, व्यवसाय या पारिवारिक कारणों से नियमित रूप से हवाई यात्रा करते हैं। उनके लिए हर यात्रा अब पहले से अधिक महंगी हो जाएगी। वहीं पर्यटन क्षेत्र पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि महंगे किराए लोगों को यात्रा की योजना बनाने से रोक सकते हैं।

एक समय था जब हवाई यात्रा को धीरे-धीरे सस्ता और सुलभ बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन मौजूदा हालात ने उस दिशा को कुछ हद तक उलट दिया है। अब स्थिति यह बन रही है कि जहां पहले ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले लोग हवाई सफर की ओर आकर्षित हो रहे थे, वहीं अब बढ़ती कीमतें उन्हें फिर से पारंपरिक विकल्पों की ओर धकेल सकती हैं।

इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह केवल अस्थायी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। यदि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और पश्चिम एशिया में तनाव कम नहीं होता, तो यह महंगाई लंबे समय तक बनी रह सकती है। ऐसे में विमानन कंपनियों के सामने चुनौती और भी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें अपने व्यवसाय को टिकाऊ बनाए रखते हुए यात्रियों को भी बनाए रखना होगा।

फिलहाल, हवाई यात्रा की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां हर फैसला संतुलन की मांग करता है—लागत और सुविधा के बीच, मुनाफे और ग्राहक संतुष्टि के बीच। लेकिन आम यात्री के लिए यह संतुलन केवल एक सवाल बनकर रह गया है—क्या वह अब भी उड़ान भर पाएगा या फिर बढ़ती कीमतें उसके सपनों को जमीन पर ही रोक देंगी।

तेल की आग में सुलगती दुनिया, 116 डॉलर के पार पहुंचे दामों ने बढ़ाई वैश्विक बेचैनी

नई दिल्ली। दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन कहे जाने वाले कच्चे तेल ने एक बार फिर वैश्विक बाजारों की नब्ज तेज कर दी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच तेल की कीमतों में आई तेज उछाल ने न केवल ऊर्जा बाजार को झकझोर दिया है, बल्कि इसका असर हर उस देश और हर उस व्यक्ति पर पड़ने लगा है, जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी किसी न किसी रूप में ईंधन पर निर्भर है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि तेल की हर बढ़ती कीमत के साथ महंगाई की नई लहर का डर भी गहराता जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में West Texas Intermediate का मई वायदा भाव तेजी के साथ 116.55 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जबकि Brent Crude का जून अनुबंध भी 111 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार करता नजर आया। यह केवल एक सामान्य वृद्धि नहीं है, बल्कि उन आशंकाओं का परिणाम है जो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर पैदा हो गई हैं। जब भी दुनिया के किसी संवेदनशील क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो उसका पहला और सबसे गहरा असर तेल की कीमतों पर ही दिखाई देता है, और इस बार भी वही तस्वीर सामने आई है।

इस उछाल के पीछे सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया में जारी तनाव और उसके संभावित विस्तार की आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई सख्त चेतावनी ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है। ऐसे माहौल में निवेशक और ट्रेडर्स दोनों ही किसी भी संभावित आपूर्ति संकट को लेकर सतर्क हो गए हैं। यही कारण है कि बाजार में जोखिम प्रीमियम तेजी से बढ़ रहा है और कीमतें लगातार ऊपर की ओर जा रही हैं।

तेल बाजार की सबसे संवेदनशील कड़ी माने जाने वाले होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी चिंता गहराई है। यह वही समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया के कुल तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। यदि यहां किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है, तो उसका असर सीधे वैश्विक आपूर्ति पर पड़ेगा और कीमतों में और अधिक उछाल आ सकता है। यही आशंका इस समय बाजार को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है।

विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा हालात केवल अस्थायी उतार-चढ़ाव नहीं हैं, बल्कि यह एक बड़े संकट की ओर इशारा भी कर सकते हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में संघर्ष की शुरुआत के बाद से 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है, जो यह बताती है कि बाजार किस तरह से जोखिम को अपने अंदर समाहित कर रहा है। यह वृद्धि केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस अनिश्चितता की तस्वीर है, जिसमें दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति घिरी हुई है।

तेल की कीमतों में यह उछाल केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। परिवहन महंगा होता है, उत्पादन लागत बढ़ती है और अंततः इसका बोझ आम उपभोक्ता पर आता है। भारत जैसे आयात पर निर्भर देश के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है, जहां तेल की हर बढ़ती कीमत सीधे महंगाई को बढ़ावा देती है और आर्थिक संतुलन को प्रभावित करती है। इस पूरे परिदृश्य में यह भी देखने वाली बात होगी कि वैश्विक शक्तियां इस तनाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाती हैं। यदि स्थिति काबू में नहीं आई, तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ेगा। वहीं यदि कूटनीतिक समाधान निकलता है, तो बाजार में कुछ राहत देखने को मिल सकती है।

फिलहाल, ऊर्जा बाजार में जो तस्वीर उभर रही है, वह यह बताती है कि दुनिया एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर चुकी है। तेल की कीमतों में यह तेजी केवल आर्थिक संकेत नहीं है, बल्कि यह उस भू-राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक भी है, जो आने वाले समय में वैश्विक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित कर सकती है। ऐसे में हर बढ़ती कीमत के साथ दुनिया की निगाहें अब सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं—क्या यह आग और भड़केगी या फिर कहीं कोई राहत की किरण दिखाई देगी।

गिरावट के अंधेरे से निकली रोशनी, बाजार ने दिखाई दमदार वापसी की ताकत

नई दिल्ली। शेयर बाजार का स्वभाव हमेशा से ही उतार-चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब यह अस्थिरता ही उसकी असली ताकत बन जाती है। ऐसा ही एक दिन घरेलू बाजार के लिए साबित हुआ, जब सुबह के भारी दबाव और गिरावट के बाद बाजार ने जिस तरह से वापसी की, उसने निवेशकों के चेहरे पर फिर से भरोसे की मुस्कान लौटा दी। शुरुआती सत्र में निराशा का माहौल था, लेकिन दिन चढ़ते-चढ़ते वही बाजार नई ऊर्जा के साथ खड़ा नजर आया और अंत में मजबूती के साथ बंद हुआ।

कारोबार की शुरुआत कमजोर संकेतों के साथ हुई थी। वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों ने निवेशकों के मन में आशंका पैदा कर दी थी, जिसका असर सीधे घरेलू सूचकांकों पर दिखा। BSE Sensex शुरुआती कारोबार में तेजी से लुढ़ककर 73,282 के स्तर तक पहुंच गया, जबकि NSE Nifty 50 भी दबाव में आकर 22,719 तक फिसल गया। इस गिरावट ने कुछ समय के लिए बाजार में बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया, जहां निवेशकों को यह लगने लगा कि शायद आज का दिन नुकसान भरा साबित हो सकता है।

लेकिन बाजार की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, निवेशकों का रुख बदलने लगा और खरीदारी का सिलसिला तेज हो गया। खासकर आईटी और मेटल सेक्टर में आई मजबूती ने पूरे बाजार का मूड बदल दिया। बड़े आईटी शेयरों में खरीदारी ने संकेत दिया कि निवेशक अभी भी दीर्घकालिक संभावनाओं को लेकर आश्वस्त हैं। Infosys, Tata

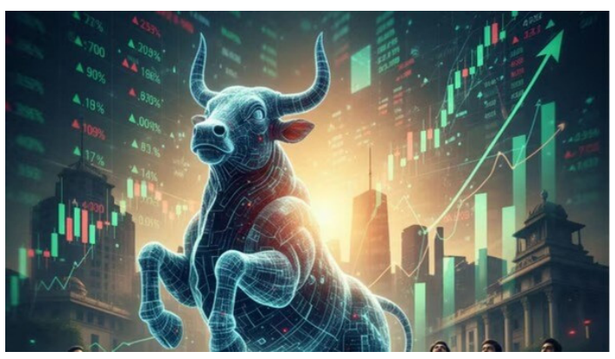

Consultancy Services और HCL Technologies जैसे दिग्गज शेयरों में आई तेजी ने बाजार को ऊपर खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसी के साथ मेटल सेक्टर में भी जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। Hindalco Industries जैसे शेयरों में उछाल ने यह संकेत दिया कि निवेशक औद्योगिक विकास और मांग में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। रियल्टी सेक्टर में भी तेजी आई, जिससे बाजार को अतिरिक्त सहारा मिला। धीरे-धीरे यह तेजी अन्य सेक्टरों में भी फैलने लगी और बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस शेयरों में भी मजबूती देखने को मिली।

हालांकि हर सेक्टर इस तेजी का हिस्सा नहीं बन पाया। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर दबाव में रहा और कुछ बड़े शेयरों में गिरावट भी दर्ज की गई। दिन के अंत में Dr. Reddy's Laboratories, Adani Enterprises, InterGlobe Aviation, Apollo Hospitals और Mahindra & Mahindra जैसे शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसके बावजूद बाजार का समग्र रुख सकारात्मक बना रहा।

दिन के कारोबार में सबसे खास बात यह रही कि बाजार ने निचले स्तर से जोरदार रिकवरी दिखाई। एक समय जब सेंसेक्स भारी गिरावट में था, वहीं बाद में इसमें करीब 1,403 अंकों तक की उछाल दर्ज की गई। अंततः BSE Sensex 509.73 अंकों की बढ़त के साथ 74,616.58 पर बंद हुआ, जबकि NSE Nifty 50 155.40 अंक चढ़कर 23,123.65 के स्तर पर पहुंच गया। यह आंकड़े केवल बढ़त नहीं दर्शाते, बल्कि निवेशकों के मनोबल में आई मजबूती को भी प्रतिबिंबित करते हैं।

इस तेजी का सबसे बड़ा लाभ निवेशकों को हुआ। दिनभर की इस सकारात्मक चाल के चलते बाजार पूंजीकरण में करीब 1.72 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप बढ़कर 429.23 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि बाजार में निवेशकों का विश्वास अभी भी बरकरार है और वे गिरावट को अवसर के रूप में देख रहे हैं।

व्यापक बाजार की बात करें तो यहां मिश्रित रुख देखने को मिला। मिडकैप इंडेक्स में हल्की बढ़त दर्ज की गई, जो यह दर्शाता है कि मध्यम आकार की कंपनियों में निवेशकों की रुचि बनी हुई है। वहीं स्मॉलकैप शेयरों में मामूली गिरावट देखने को मिली, जिससे यह संकेत मिलता है कि निवेशक अभी भी जोखिम को लेकर सतर्क हैं और चुनिंदा निवेश ही कर रहे हैं।

पूरे दिन के उतार-चढ़ाव ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि शेयर बाजार केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह निवेशकों की भावनाओं, उम्मीदों और रणनीतियों का प्रतिबिंब भी है। सुबह की गिरावट ने जहां डर पैदा किया, वहीं दोपहर की तेजी ने उस डर को उम्मीद में बदल दिया।

इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि बाजार में स्थिरता के लिए केवल सकारात्मक खबरें ही जरूरी नहीं होतीं, बल्कि निवेशकों का विश्वास और सही समय पर किया गया निवेश भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल, बाजार की यह वापसी यह संकेत देती है कि आर्थिक मोर्चे पर उम्मीदें अभी जिंदा हैं और निवेशक भविष्य को लेकर आशावादी बने हुए हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह तेजी बरकरार रहती है या बाजार फिर किसी नई चुनौती का सामना करता है, लेकिन फिलहाल के लिए यह दिन निवेशकों के लिए राहत और आत्मविश्वास दोनों लेकर आया है।